2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद से रूस ने सीरिया से जुड़े मुद्दों पर 14 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वह सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी देश है।

भेदभाव खत्म करने को हटाया गया अनुच्छेद 370 : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार से लड़ने और जातीय व धार्मिक भेदभाव खत्म करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत लिया गया था।

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए विल्सन ने कहा, 'दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में अमेरिकी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को सफल होते देखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।' अगस्त में विल्सन ने मुंबई की यात्रा की थी और 26/11 आतंकी हमले वाले स्थानों पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। उन्होंने कहा, '15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस संबोधन बेहद प्रेरणादायी था।' विल्सन ने आगे कहा, 'सितंबर में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहना भी असाधारण था जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। 52 हजार लोगों की मौजूदगी के साथ अमेरिका के इतिहास में किसी देश के प्रमुख का यह सबसे भव्य स्वागत समारोह था।'

गांधी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश

वाशिंगटन, प्रेट्र: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता व सांसद जॉन लुईस द्वारा पेश बिल में इस कार्य के लिए अगले पांच वर्ष में एक हजार करोड़ से अधिक रुपये के अनुदान की मांग की गई है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पेश 'हाउस बिल (एचआर 5517)' दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मित्रता और गांधी एवं लूथर किंग जूनियर के विचारों और योगदान को दर्शाता है।

गांधीवाद के प्रोत्साहन के लिए पेश इस विधेयक के अन्य प्रस्तावों में गांधी-किंग डेवेलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना करना भी शामिल है, जिसे भारतीय कानूनों के तहत 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआइडी)' द्वारा गठित किया जाएगा। विधेयक में इस फाउंडेशन के लिए यूएसएआइडी को अगले 5 वर्ष तक हर वर्ष तीन करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 210 करोड़ रुपये देने की मांग की गई है।

विधेयक में कहा गया, यह फाउंडेशन

▸ अगले पांच वर्ष के लिए एक हजार करोड़ से अधिक अनुदान देने की मांग

अमेरिकी संसद। फाइल

अमेरिका और भारत की सरकारों द्वारा गठित एक परिषद होगा, जो स्वास्थ्य, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान मुहैया कराएगी। इस विधेयक को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद डॉ. एमी बेरा, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल के अलावा ब्रेंडा लॉरेंस, ब्रांड शेरमैन और जेम्स मैकगवर्न का भी समर्थन हासिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा, यह भारत और अमेरिका के बीच 'घनिष्ठ सांस्कृतिक और वैचारिक' संबंधों को मजबूत करता है।

अकाल तख्त के जत्थेदार को भेजा जाएगा अमेरिकी संसद का प्रस्ताव

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में सिखों के सम्मान में पारित किए गए एक प्रस्ताव की विशेष प्रति अकाल तख्त के जत्थेदार को भेजा जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इसकी प्रतियां भेजी जाएंगी। इस प्रस्ताव में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के साथ ही अमेरिका के विकास में सिखों के योगदान की भी सराहना की गई है।

रिपब्लिकन सांसद टॉड यंग और डेमोक्रेटिक सांसद बेन कार्डिन की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को गत 14 नवंबर को सर्वसम्मिति से पारित किया गया था। यंग ने बताया, 'हम अकाल तख्त के जत्थेदार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समति के अध्यक्ष को प्रस्ताव की प्रतियां भेज रहे हैं। प्रस्ताव की प्रतियों के साथ पत्र भी इंडियाना में रहने वाले जानेमाने सिख नेता गुरिंदर सिंह खालसा को सौंपा गया है।' प्रस्ताव की प्रतियों और पत्र लेकर इसी माह भारत की यात्रा पर आने वाले गुरिंदर ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले करीब दस लाख सिखों के लिए यह गर्व की बात है।

सीनेट में किया गया पेश

सीनेट में गत 31 अक्टूबर को प्रस्ताव पेश करते समय यंग ने कहा था, 'यह प्रस्ताव अमेरिकी सिखों का सम्मान करता है, जो हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता का अहम हिस्सा हैं।' जबकि कार्डिन ने सिखों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही नस्ली और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने के लिए सिखों के साहस की सराहना की थी।

विदेशी मंत्री पर सांसद से मिलने के लिए डाला गया था दबाव

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल से विदेश मंत्री एस जयशंकर के नहीं मिलने के मुद्दे पर भारत का रुख सामने आया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने जयशंकर को जयपाल से बैठक करने पर जोर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया। खास बात यह है कि जयपाल विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाली समिति की सदस्य भी नहीं थीं।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। दरअसल, विदेश मंत्री से सीनेट और विदेश मामलों की संसदीय समितियों के नेताओं से मिलने का आग्रह किया गया था। सीनेट नेताओं के साथ बातचीत खुले मन से हुई। वहीं विदेश मामलों की संसदीय समितियों के कुछ नेता जयशंकर से मिले और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान संसदीय समितियों ने बिना विदेश मंत्री की सहमति कुछ उन लोगों को बुला रखा था, जिनका कश्मीर जैसे मुद्दे पर रुख सर्वविदित है। किसी भी देश के विदेश मंत्री को किसी विशेष राजनेता से मिलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। गुरुवार को जयशंकर ने कहा था कि उन्हें जयपाल से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि प्रमिला जयपाल प्रतिनिधि सभा में कश्मीर मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाई थीं और भारत से जम्मू-कश्मीर में लागू प्रतिबंधों में छूट देने का आग्रह किया था।

जयपाल के समर्थन में उतरे सैंडर्स और वॉरेन

वाशिंगटन, प्रेट्र: डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की मजबूत दावेदार बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन सहित दो अन्य अमेरिकी सांसद अब जयपाल के समर्थन में उतर आए हैं। सैंडर्स, वॉरेन और अन्य सांसदों ने शुक्रवार को जयपाल के समर्थन में ट्वीट किया, जिसमें जयशंकर और भारत पर अमेरिकी सांसद की आवाज को खामोश कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। वॉरेन ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका और भारत महत्वपूर्ण साझेदार हैं, लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब बातचीत में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए।

रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों के विधेयक को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी

बड़ा मामला ▸ राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून पर किए दस्तखत, बढ़ेगा देश का रक्षा बजट

एनडीएए करेगा यूरोपीय ऊर्जा की जरूरतों की रक्षा

वाशिंगटन, आइएएनएस: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध के प्रावधान वाले 738 अरब डॉलर (करीब 52 लाख करोड़ रुपये) के रक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए) 2020 को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही अमेरिकी सैन्य खर्च में लगभग 20 अरब डॉलर (डेढ़ लाख करोड़ रुपये) की वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक पर शुक्रवार रात वाशिंगटन के निकट ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर हस्ताक्षर किए गए।

विधेयक में कहा गया है कि एनडीएए रूसी ऊर्जा पाइपलाइनों वाली परियोजना - नार्ड स्ट्रीम 2 और तुर्कस्ट्रीम पर प्रतिबंध लगाकर यूरोपीय ऊर्जा की जरूरतों की रक्षा करेगा। विधेयक में तुर्की द्वारा रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एस-400 के अधिग्रहण के खिलाफ उसे अमेरिकी नेतृत्व वाले एफ-35 लड़ाकू जेट कार्यक्रम से बाहर रखने के फैसले को दोबारा लागू किया गया है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लेवरोव ने पिछले सप्ताह

रूस और तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने वाले राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीडीए)-2020 पर हस्ताक्षर करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस मौके पर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप (बाएं) और उपराष्ट्रपति माइक पेंस (दाएं) भी मौजूद रहे। एएफपी

वाशिंगटन में कहा था कि ना तो नार्ड स्ट्रीम 2 और ना ही तुर्कस्ट्रीम परियोजना को बंद किया जाएगा। दरअसल, एनडीएए विवेकाधीन कोष के तहत अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के लिए लगभग 635 अरब डॉलर (45 लाख करोड़ रुपये) के बजट की व्यवस्था करता है। इतना ही नहीं इसमें 3.1 फीसद वेतन वृद्धि भी शामिल है, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। बिल में स्पेस फोर्स (अंतरिक्ष सेना) की स्थापना भी शामिल है।

रूस और जर्मनी ने परियोजना पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई : रूस ओर तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने वाले विधेयक को मंजूरी देने के बाद शुक्रवार को जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से फोन पर बात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गन ऑर्टागस ने कहा कि पोंपियो ने दोनों परियोजनाओं के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है। हालांकि इसके बावजूद रूस और जर्मनी ने नार्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि की है। बता दें कि पिछले सप्ताह जर्मन-रूसी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जोर देकर कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोनों ही परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं और अगर विधेयक को मंजूरी मिलती है तो अमेरिका के खिलाफ जवाबी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

अमेरिका बनाएगा अपनी अंतरिक्ष सेना : रूस और चीन से 21वीं सदी में मिलने वाली रणनीतिक चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने रक्षा विभाग के तहत एक अंतरिक्ष सेना के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सेना की पांच अन्य शाखाओं की तरह काम करेगा। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (एनडीएए) 2020 पर दस्तखत के दौरान ट्रंप ने वहां मौजूद सैन्य अफसरों से कहा था कि भविष्य में अंतरिक्ष नया युद्धक्षेत्र बनेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा।

पाकिस्तान में ईशनिंदा में मुस्लिम प्रोफेसर जुनैद को मौत की सजा

▸ फेसबुक पोस्ट लिखने पर हुई कार्रवाई, पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

▸ जुनैद के वकील राशिद रहमान की उनके दफ्तर में ही कर दी गई थी हत्या

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में ईशनिंदा संबंधी फेसबुक पोस्ट लिखने पर एक मुस्लिम प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई गई है। प्रोफेसर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। डॉन अखबार के अनुसार, पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर स्थित बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी (बीजेडयू) में अंग्रेजी के प्रोफेसर जुनैद हाफिज के खिलाफ ईशनिंदा का मामला दाखिल किया गया था। पुलिस ने उन्हें 13 मार्च, 2013 को गिरफ्तार किया था। 2014 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मुल्तान की सत्र अदालत के जज कासिफ कयूम ने शनिवार को जुनैद को मौत की सजा सुनाई। मई 2014 में जुनैद के वकील राशिद रहमान की उनके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस साल के प्रारंभ में जुनैद के माता-पिता ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा से अपने बेटे के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा पिछले छह साल से ईशनिंदा के झूठे आरोप में मुल्तान की सेंट्रल जेल में बंद है।

पाकिस्तान में ईशनिंदा काफी संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे मामलों में अक्सर ही हिंसा तक भड़क उठती है। इस्लाम की निंदा या अपमान करने का दोषी या यहां तक आरोपी पर भी हिंसक घटनाओं और हत्या का खतरा रहता है। हालांकि, अधिकार समूहों का कहना है निजी खुन्नस दूर करने की आड़ में अक्सर ईशनिंदा कानून का उल्लंघन किया जाता है।

236 हॉवित्जर तोप खरीदेगा पाक

नई दिल्ली, आइएएनएस : जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बनी तनाव की स्थिति के बीच पाकिस्तान ने चीन से 236 हॉवित्जर तोप खरीदने का फैसला किया है। इससे उसकी हमले की क्षमता में खासा इजाफा होगा।

पाकिस्तान ने एसएच-15 हॉवित्जर तोप का सौदा चाइना नॉर्दन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ किया है। इस सौदे के साथ ही पाकिस्तान को तोप के निर्माण की तकनीक भी मिलेगी। पाकिस्तान इस सौदे की पहली किश्त के रूप में दो करोड़ डॉलर की धनराशि का भुगतान कर चुका है। सूत्रों के अनुसार एक साल के भीतर ये तोपें प्राप्त कर पाकिस्तान इन्हें नियंत्रण रेखा के नजदीक तैनात करेगा। पता चला है कि इन तोपों से छोटे परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा छोटे आकार के परमाणु बम बनाने की काफी चर्चा है। ये सीमित इलाके में भयानक बर्बादी फैलाने वाले होते हैं। पाकिस्तानी सेना ने एचएस-15 तोप का इसी साल कराची में परीक्षण किया था। परीक्षण में

प्रतीकात्मक

सेना ने उसे उपयुक्त पाया और सरकार से खरीदने के लिए सिफारिश की थी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में तोप बनाने का कारखाना स्थापित करने में भी सहयोग दे रही है। जबकि चीनी कंपनी टैक्सिला पाकिस्तान के मुख्य युद्धक टैंक 85-2 एपी में बदलाव कर रही है। 106 टैंकों की क्षमता में बढ़ोतरी की योजना है। पाकिस्तानी सेना के पास ऐसे कुल 268 टैंक हैं। 1990 में इनकी चीन से खरीद की गई थी।

इमरान खान को सता रहा भारत के हमले का डर

▸ आशंकित पाक पीएम ने कहा, नागरिकता कानून के विरोध से बन रहे हालात

▸ ताबड़तोड़ ट्वीट कर मोदी सरकार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे पर चलने का लगाया आरोप

इस्लामाबाद, प्रेट्र : नागरिकता कानून के विरोध को ठंडा करने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान पर हमले जैसा कदम उठा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही है।

लगातार कई ट्वीट कर इमरान ने कहा, भारत की मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे पर चल रही है। नागरिकता कानून में बदलाव इसीलिए किया गया है। सेकुलर सोच वाले लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और अब यह बड़ा आंदोलन बन गया है। इमरान ने कहा कि भारत जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की टिप्पणी यही संकेत करती है। उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने बुधवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव कभी भी बढ़ सकता है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

जनरल रावत का बयान पाकिस्तानी सेना के बार-बार के संघर्षविराम उल्लंघन की बाबत आया था। जम्मू-कश्मीर से अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना बार-बार सीमापार से फायरिंग कर उकसावे की कोशिश कर रही है। ध्यान बांटकर आतंकियों को भारत में भेजना चाह रही है।

इमरान खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेताया है कि भारत ने पाकिस्तानी धरती के भीतर अब कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान के पास उसका करारा जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भारत घरेलू समस्या से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर सकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी उसे रोके। इमरान इससे पहले भी भारत के नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि जनरल रावत ने सैन्य कार्रवाई का बयान देकर भारत की घरेलू समस्या से ध्यान हटाने का प्रयास किया है।

फ्रांसीसी सर्जन पर 349 बच्चों के यौन उत्पीड़न का संदेह

लोरिएंट, एएफपी : एक सेवानिवृत्त फ्रांसीसी सर्जन ने अपने 30 साल के सेवाकाल के दौरान कम से कम 349 बच्चों के साथ दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न किया होगा। फ्रांस में बाल यौन उत्पीड़न के अभी तक के सबसे बड़े मामले के अभियोजक ने यह जानकारी दी है। चार पीड़ित बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपित 68 वर्षीय जोएल ले स्कोउर्नेक के खिलाफ मार्च से सुनवाई शुरू होगी।

आरोपित सर्जन 30 वर्षों तक मध्य और पश्चिम के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत रहा। उसके खिलाफ आरोप में पूरे सेवाकाल को समेटा जा सकता है। उसके खिलाफ आरोपों में पड़ोस में रहने वाली एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के अलावा एक एक युवा रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म और दूसरे का यौन उत्पीड़न शामिल है।

एक बाल रोगी के यौन उत्पीड़न से उसका कृत्य सामने आया है। इस मामले में उसके खिलाफ आरोप लगने के बाद जांचकर्ताओं ने गोपनीय डायरियां बरामद कीं जिसमें ले स्कोउर्नेक के सैकड़ों बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य का पता चला।

चीन को आर्थिक मदद बंद करने की मांग

वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक मुख्यालय के सामने तुर्की नेशनल एवेकिंग मूवमेंट (ईटीएनएएम) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चीन के उइगर मुस्लिमों के इलाकों में चल रहे चाइनीज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तत्काल बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक इन सेंटर्स को 50 मिलियन डॉलर (करीब साढ़े तीन अरब रुपये) की आर्थिक मदद देता है। एएफपी

सीरिया पर आए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर चीन-रूस का वीटो

संयुक्त राष्ट्र, एएफपी : हिंसाग्रस्त सीरिया के चालीस लाख लोगों को मानवीय सहायता एक वर्ष के लिए बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके रोक दिया है। फिलहाल सीरिया में मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र के जांच केंद्रों से होकर पहुंचाई जाती है और इसके लिए बशर अल असद सरकार की अनुमति नहीं लेनी होती है।

दरअसल, मौजूदा सुविधा की समय-सीमा अगले वर्ष 10 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसी अवधि को बढ़ाए जाने के लिए जर्मनी, बेल्जियम और कुवैत ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को परिषद के 13 सदस्यों का समर्थन मिला था, लेकिन इस पर रूस और चीन ने वीटो कर इसे रोक दिया। बता दें कि इस संबंध में रूस ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जांच केंद्रों की संख्या को कम करके छह महीने के विस्तार की अनुमति देने की बात कही गई थी। हालांकि उसके प्रस्ताव को मात्र नौ वोट मिले। रूस, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी और प्रमुख समर्थक देश है।

बड़ा फैसला

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस फैसले से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहूदी देश के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया है

फलस्तीन में युद्ध अपराधों की जांच करेगा आइसीसी

▸ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मुख्य अभियोजक ने किया एलान

▸ इजरायल ने दी तीखी प्रतिक्रिया तो अमेरिका ने भी की आलोचना

हेग, एएफपी : इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसीसी) की मुख्य अभियोजक फातोउ बेनसाउदा ने कहा कि वह फलस्तीन क्षेत्रों में हुए कथित युद्ध अपराधों की विस्तृत जांच शुरू करना चाहती हैं। उनके इस एलान पर इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी ने भी इसकी आलोचना की है। जबकि फलस्तीन ने इस कदम का स्वागत किया है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस फैसले से हेग स्थित आइसीसी यहूदी देश के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया है। इजरायल साल 2002 में गठित इस अंतरराष्ट्रीय अदालत का हिस्सा बनने से इन्कार करता रहा है। इसके पहले शुक्रवार को आइसीसी की मुख्य अभियोजक फातोउ ने एक बयान में कहा, 'मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि फलस्तीन के हालात की जांच शुरू करने का वाजिब आधार है। मुझे लगता है कि पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी समेत वेस्ट बैंक में युद्ध अपराध किए गए या हो रहे हैं।' हालांकि उन्होंने कथित युद्ध अपराधों को अंजाम देने वालों का कोई ब्योरा नहीं दिया।

आइसीसी के जजों को गिरफ्तार करने की दी थी धमकी

इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की उस धमकी से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने पिछले साल कहा था कि इजरायल या अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो आइसीसी के जजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

2015 में हुई थी प्रारंभिक जांच

आइसीसी की मुख्य अभियोजक फातोउ ने इजरायल और फलस्तीनी क्षेत्रों में हुए कथित युद्ध अपराधों की जनवरी 2015 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। 2014 में हुए गाजा युद्ध में फलस्तीन की तरफ 2251 लोगों की मौत हुई थी। इनमें ज्यादातर नागरिक थे। जबकि इजरायल में 74 मौत हुई थी। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद आइसीसी की विस्तृत जांच संभव नहीं हो पाई थी।

फातोउ ने बताया कि वह विस्तृत जांच शुरू करने से पहले आइसीसी से उस क्षेत्र की जानकारी लेंगी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस जांच को शुरू करने के लिए जजों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आइसीसी से 2015 में जुड़ने वाले फलस्तीन ने जांच का अनुरोध कर रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, 'हम इजरायल को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि फलस्तीन संप्रभु देश नहीं है, इसलिए वह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता।' इजरायल, अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है।

लंदन में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारी

लंदन, प्रेट्र : भारत में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ शनिवार को लंदन में 'पार्लियामेंट स्क्वायर' पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र और अन्य लोग एकत्र हुए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन 'भारतीय संविधान को बचाओ' के संदेश के साथ किया गया।

इसमें ब्रिटेन स्थित कई दक्षिण एशियाई संगठन जुटे। उनके हाथों में तिरंगा ध्वज था और तख्तियां थीं, जिन पर सीएए एवं एनआरसी वापस लेने की मांग की गई थी। इस बीच, शनिवार को ब्रिटेन में कई विश्वविद्यालय परिसरों में सिलसिलेवार प्रदर्शन हुए। बुधवार को ब्रिटेन भर से जुटे सैकड़ों लोगों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर तख्तियां और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की भारत सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिया जाए।

'अमेरिका के बेबुनियाद आरोपों से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा'

▸ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर उत्तर कोरिया ने किया पलटवार

सियोल, रायटर : मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के अमेरिका के आरोपों पर उत्तर कोरिया ने पलटवार किया है। कहा कि इन घृणास्पद आरोपों से कोरियाई प्रायद्वीप में केवल तनाव बढ़ेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान वहां की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए पर आया है।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उत्तर कोरिया की सरकारी व्यवस्था को बदनाम करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की निंदा की है। कहा है कि वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सिलसिला दशकों से चल रहा है, जो निंदनीय है। संयुक्त राष्ट्र आमसभा में बुधवार को इस सिलसिले में दर्जनों देशों द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया जिसमें अमेरिका भी शामिल था। उत्तर कोरिया की ओर से यह प्रतिक्रिया तब

उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की यूएन ने भी निंदा की थी। फाइल

आई है जब उत्तर कोरिया मामलों के विशेष दूत स्टीफन बीगन ने उससे परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित वार्ता में फिर से शामिल होने का अनुरोध किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी शुक्रवार को उम्मीद जताई कि अमेरिका और उत्तर कोरिया जल्द ही वार्ता की टेबल पर होंगे और उसे अपेक्षित सफलता मिलेगी।